डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जनवरी, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 जनवरी, 2020

| वर्ष 63 | अंक 15 | भोपाल | 1 जनवरी, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

जड़ी-बूटियों पर रिसर्च के लिये फण्ड बनाए लघु वनोपज संघ : सहकारी मंत्री डॉ. सिंह

भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का शुभारंभ

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के मुख्य आतिथ्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री आरिफ अकील की अध्यक्षता, जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा और अध्यक्ष राज्य वनोपज संघ श्री वीरेन्द्र गिरि गोस्वामी के विशिष्ट आतिथ्य में भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड पर अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला शुरू हुआ था। वन विभाग और राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित वन मेले में देश–प्रदेश, भूटान और नेपाल के प्रतिनिधि भाग लिया। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे देश में हजारों वर्ष से जड़ी–बूटियों से इलाज की परम्परा रही है। आयुर्वेद की विदेशों और देश में पुनः बढ़ती लोकप्रियता उसकी विश्वसनीयता को सुदृढ़ करती है। उन्होंने हर्बल मेले के माध्यम से जन–जागरूकता के प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि लघु वनोपज संघ जड़ी–बूटियों के रिसर्च के लिये फण्ड स्थापित करे। डॉ. सिंह ने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में धनवंतरी की चिकित्सा विधि और सुश्रुत की शल्य–चिकित्सा विद्यमान थी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह ने राज्य लघु वनोपज संघ की स्थापना कर वनोपज संग्राहकों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने का नेक काम किया। डॉ. सिंह ने आदिवासियों के भोलेपन का जिक्र करते हुए कहा कि संघ की स्थापना के पहले आदिवासी मात्र आधा किलो अनाज के बदले बिचौलियों को 2–3 किलो चिरोंजी दे दिया करते थे। गैस त्रासदी मंत्री श्री आरिफ अकील ने कहा कि भोपालवासियों को सालभर हर्बल मेले का इंतजार रहता है। उन्होंने मेले में भाग लेने वाली विभिन्न आयुर्वेदिक कम्पनियों और वैद्यों से गैस पीड़ित मरीजों की किडनी, ह्रदय आदि से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में वनोपज किसानी के साथ आमदनी का एक अतिरिक्त साधन है। वन में रहने वाले आदिवासियों की आय बढ़ने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अपर मुख्य सचिव श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. यू. प्रकाशम, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ श्री एस.के. मण्डल, विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह शेरा, संघ के संचालक मण्डल के सदस्य, बड़ी संख्या में अधिकारी–कर्मचारी, वन समितियों के सदस्य और नागरिक उपस्थित थे।

सहकारिता जिन्दगी का तौर तरीका

यद्यपि ग्रामवासी वस्तुओं का निर्माण अपने घरों में कर सकते हैं, तथापि, उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है और लाभ को उनमें बांटा जा सकता हैं। ग्रामीण लोग पर्यवेक्षण में और योजना के अनुसार कार्य कर सकते हैं। कच्चा माल सॉझे भंडार से दिया जा सकता हैं। यदि सहकारी प्रयास के लिये इच्छा शक्ति पैदा कर ली जाती है तो श्रम विभाजन, समय की बचत और कार्य में कुशलता लाने के लिये अवश्य प्रचुर अवसर विद्यमान हैं।

– महात्मा गांधी

ऑन लाइन व्यापार से किसानों को मिलेगा उपज का बेहतर मूल्य : सहकारिता मंत्री

सहकारिता विभाग ने तैयार किया "एग्री व्यापार" एप

Agrivyapar Markfed

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलवाने के लिए "एग्री व्यापार" एप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज व्यापारी को सीधे ऑनलाइन बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा बनाए गए इस एप पर अभी तक15 हजार 27 किसान, 221 विपणन समितियां, 4 कमोडिटी एक्सचेंज तथा 40 डायरेक्ट बायर्स "एग्री व्यापार एप" पर अपना पंजीयन करवा चुके हैं।

मंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि सहकारिता विभाग किसानों को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की खाद–बीज उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें फसल का अधिकतम मूल्य दिलवाने के लिये कृतसंकल्पित है। इसके लिए "एग्री व्यापार" एप के माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस डिजीटल प्लेटफार्म पर किसानों के साथ ही देश–विदेश के व्यापारी एवं उपभोक्ता भी जुड़ रहे हैं। इस एप पर किसानों की उपज के व्यापक प्रदर्शन के साथ ही ग्राहक की पसंद एवं कस्टमर फीड बैक की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

"एग्री व्यापार" एप के उपयोग का तरीका

गूगल प्ले स्टोर से इस एप को मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद एप पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के बाद किसान को अपनी फसल की मात्रा एवं विवरण का इसमें उल्लेख करना होगा। इसी प्रकार व्यापारी/क्रेता को अपनी आवश्यकता इस एप पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद किसान क्रेता के साथ अपनी फसल के मूल्य का सीधे सौदा कर सकेंगे। किसान अपनी फसल की ऑनलाइन बोली भी लगा सकेंगे। इसमें बिचौलियों के लिये कोई स्थान नहीं है। किसान सीधे क्रेता से व्यापार करेंगे। सहकारी विपणन समितियां इस कार्य में किसानों की मदद करेंगी।

मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती ने मंत्रालय में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों से "जय किसान फसल ऋण माफी योजना" के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का समापन

दुनिया का चिकित्सा विज्ञान भारतीय ज्ञान पद्धति की देन

भोपाल। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने लाल परेड मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला समापन समारोह में कहा है कि दुनिया का चिकित्सा विज्ञान, भारतीय ज्ञान परम्परा की देन है। इसके जन्मदाता थे धनवंतरि गुरु। सारी दुनिया ने फॉदर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को माना है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में चिकित्सा विज्ञान सेवा विधि थी जो दुर्भाग्य से पाश्चात्य के बाजारवाद का शिकार हो गई। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने समारोह की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने हर्बल मेला स्मारिका का विमोचन किया।

राज्यपाल ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्यति नाड़ी तंत्र और श्वसन पर आधारित थी। नाड़ी वैद्य बिना किसी उपकरण के सारे शरीर का हाल जान लेते थे। योग से श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया ने भारतीय योग का महत्व स्वीकार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जड़ी–बूटियों की माँग बढ़ रही है। राज्यपाल ने कहा कि वनोत्पादों के विपणन की बेहतर व्यवस्थाएँ और वनों की सुरक्षा के साथ वनवासियों के सशक्तिकरण के प्रयास अब जरूरी हैं।

श्री लालजी टंडन ने कहा कि भारतीय ऋषि–मुनियों ने चिकित्सा ज्ञान के उपयोग के उपायों को स्पष्ट किया है। भारतीय वैद्य चिकित्सा की मान्यता थी कि यदि उनके दरवाजे से पैसे के अभाव में कोई रोगी बिना उपचार के चला गया, तो उनका समस्त ज्ञान समाप्त हो जाएगा। इसी मान्यता पर भारतीय औषधियाँ प्रमुखतः दो समूहों में बंटी थी, काष्ठ आधारित और धातु आधारित। काष्ठ आधारित औषधियाँ वनोत्पादों से बनती थीं और निःशुल्क उपलब्ध होती थीं। धातु आधारित औषधियाँ महँगे रत्नों और धातुओं से बनने के कारण तेज असर करती थीं। रोग का उपचार दोनों से होता था। वैद्य रोगी की आर्थिक स्थिति के अनुसार उनका उपयोग करते थे। श्री टंडन ने चिकित्सकों का आव्हान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने में करें।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित होगा 282 करोड़ बोनस

वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में वन और वन्य–जीव संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वनों से प्रदेश के 11 लाख परिवारों को रोजगार मिल रहा है। वनवासियों को वन उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, सरकार इसके लिये प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 282 करोड़ रूपये बोनस वितरण शीघ्र किया जाएगा। मंत्री श्री सिंघार ने कहा कि मध्यप्रदेश को औषधीय उत्पादों का नम्बर वन राज्य बनाने का प्रयास है। वंदन योजना के माध्यम से दो–तीन सौ परिवारों के कलस्टर बनाकर वनोत्पाद प्र–संस्करण की इकाई स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इको सिस्टम का संरक्षण मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य का आधार है। समारोह में राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र गिरि ने बताया कि महिला सशक्तीकरण के लिये एक हजार 72 समितियों में महिलाओं को संचालक बनाया गया है। प्रबंध संचालक लघुवनोपज संघ श्री एस.के. मंडल ने अतिथियों का अभिवादन किया। लघु वनोपज संघ के उपाध्यक्ष श्री रामनारायण साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री यू. प्रकाशम सहित बड़ी संख्या में हर्बल प्रेमी तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे।

डिपाजिट एवं ऋण दोनों बढ़ाने के प्रयास करें : प्रशासक अशोक सिंह

अपेक्स बैंक के शाखा प्रबंधकों की बैठक में दिये निर्देश

भोपाल। अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री अशोक सिंह ने मध्यप्रदेश के समस्त शाखा प्रबंधकों की भोपाल के सुभाष यादव भवन में बैठक ली, जिसमें शाखाओं को ऋण वितरण, संस्थागत एवं व्यक्तिगत डिपाजिट, ग्राहकों की संख्या साथ–साथ बैंकिंग के हर पहलू पर सहज रूप से चर्चा करते हुए निर्देश दिये कि आप लोगों की हर परेशानी में बैंक के मुखिया होने के नाते में आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन बैंक की कार्यप्रणाली को वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के युग में सुदृढ़ बनाने की दिशा में आपको कमर कसकर ईमानदारी से प्रयास करना होंगे ।

उन्होंने अपेक्षा की कि अपने अन्तर्मन से संकल्प लेकर आप लोग अपने जिले में जाईये और लोगों से व्यक्गित सम्पर्क कर अपने स्टॉफ के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करके अपनी शाखा का व्यक्तिगत डिपाजिट बढाने तथा ऋण का अधिक से अधिक वितरण करने की दिशा में आवश्यक पहल प्रारंभ करें। साथ ही विश्वास व्यक्त किया कि यदि आप अपने कार्य–व्यवहार में सहजता और विनम्रता के साथ प्रयास करेंगे तो आप लोग बैंक की प्रगति में अपना योगदान देने में अवश्य ही सफल होंगे ।

उन्होंने पुराने के साथ ही साथ नये ऋण प्रकरणों के एन.पी.ए. होने पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया जिन अधिकारी/कर्मचारी ने जिस शाखा में एन.पी.ए. वाले प्रकरण स्वीकृत किये थे, उन्हें ही विशेष रूप से उस ऋण प्रकरण की वसूली करने हेतु उक्त शाखा में भेजा जावे, ताकि वे अपने कार्यकाल के दौरान स्वीकृत किये गये उक्त ऋण की वसूली में अहम भूमिका निर्वाह कर सकें ।

बैठक के आरंभ में बैंक के प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा ने शाखा प्रबंधकों के साथ चर्चा के दौरान बैंक के डिपाजिट, ऋण वितरण एवं एन.पी.ए. की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि बैंक की प्रगति की दिशा में शाखा प्रबंधक द्वारा हरसंभव सकारात्मक प्रयास किये जाना चाहिये। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बैंकिंग परिचालन श्री यतीश त्रिपाठी ने निर्देश दिये कि बैंक को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अवश्य ही ईमानदारी और समर्पण भाव से काम करना आवश्यक है। आप सभी लोग नियमित योजनाबद्ध रूप से इस दिशा में प्रयास आरंभ करें । बैठक में प्रदेश के समस्त संभागीय एवं अमानत शाखा प्रबंधकों के साथ बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे । बैठक का संचालन सहायक महाप्रबंधक लेखा/वित्त प्रबंधन श्री उमेश राहंगडाले ने किया ।

डायल 100 की तर्ज पर कॉल सेन्टर 1912

विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए डायल 100 की तर्ज पर कॉल सेन्टर 1912 स्थापित किया गया है। जनवरी 2019 से अब तक इसमें प्राप्त 31 लाख 65 हजार 727 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शिकायतों के निराकरण के बाद उपभोक्ताओं से फीडबेक भी लिया जाता है।

गांधी जी के विचारों को आचरण में उतारे तभी विकास संभव : श्री नामदेव

राज्य सहकारी संघ में गांधी दर्शन में ट्रस्टीशिप तथा सहकारी प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित

भोपाल। गांधी जी के विचारों को व्यक्ति आत्मसात करेगा तभी राष्ट्र का विकास संभव है। उक्त उद्‌गार गांधी भवन ट्रस्ट के सचिव श्री दयाराम नामदेव ने राष्ट्रीय सहकारी संघ के सहयोग से म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा गांधी दर्शन में ट्रस्टीशिप और सहकारिता विषय पर आयोजित जिला स्तरीय सहकारी कार्यशाला में व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त अपर आयुक्त श्री पी.डी. मिश्रा ने की।

श्री नामदेव ने जैविक खैती पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षैत्रों में जैविक खेती करें जिससे स्वस्थ समाज का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी, बांस तथा मिट्‌टी के सामान निर्माण करे जिससे मशीनीकरण के स्थान पर हाथों की कला विकसित होगी। उन्होंने कहा कि संगठित होकर कार्य कर श्रम का महत्व बढ़ाये जिससे सबका विकास होगा। मजदूर और मालिक का अंतर मिटाये यही ट्रस्टीशिप है। आज मानवीय संस्कृति का विकास जरूरी है। आज बाजार है लेकिन विश्वास जगाना है। स्व–निर्मित सामानों में कलात्मकता के साथ गुणवत्ता जरूरी है इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने कार्यक्रम की रूपरेखा तथा महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्‌बोधन में श्री पी.डी. मिश्रा ने कहा कि ट्रस्टीशिप का महत्व है सौंप दिया। रखवाले बनकर रहे स्वामित्व का भाव न रखे। सहकारिता में भी सबका स्वामित्व होता है। कार्यक्रम को श्री अरूण कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन श्री अरूण कुमार जोशी ने तथा आभार श्री संतोष येड़े ने व्यक्त किया।

नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

इन्दौर। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर द्वारा नर्मदा नगर (पुनासा डेम) जिला खण्डवा में मत्स्य पालन सहकारी संस्थाओं के संचालकों हेतु तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मत्स्य पालन सहकारी संस्थाओं के 30 पदाधिकारियों ने भागीदारी की। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये श्री के.एल. राठौर ने सहकारिता के सैद्धान्तिक पहलु एवं सहकारी संस्थाओं की प्रबंध व्यवस्था पर जानकारी प्रदान की। म.प्र. मत्स्य सहकारी संघ मर्यादित के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.के. खरे ने म.प्र. शासन की योजनाऐं बताई। सहायक प्रबंधक सुश्री नीतू गर्ग ने संघ द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। सिमरन ग्रुप के श्री अभिमन्यु तिवारी ने ग्रुप द्वारा हर सम्भव सदस्यों को सुविधा देने का आश्वासन दिया। केन्द्र के प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा ने पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि सहकारिता मानव के सर्वांगिण विकास का आधार है। हमने समय काल परिस्थिति अनुसार नैतिक मूल्यों व सिद्धान्तों को आत्मसात कर सहयोग की भावना से सभ्यता व संस्कृति का विकास किया है व सहकारिता में नये–नये आयाम स्थापित किये है। जिला सहकारी संघ खण्डवा के प्रबंधक श्री मेहताब सिंह भदौरिया ने संघ की योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम का समापन श्री के. पाटनकर, उपायुक्त सहकारिता एवं प्रभारी अधिकारी जिला सहकारी संघ खण्डवा द्वारा बैग वितरण कर किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता ने अपने उद्‌बोधन में मत्स्य पालन करने वाले मछुआरों की बचत हेतु सहकारी संस्था बनाने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा ने व आभार श्री जिला सहकारी संघ खण्डवा के प्रबंधक श्री मेहताब सिंह भदौरिया ने माना।

वसूली, बिक्री अधिकारियों तथा परिसमापकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल में सहकारिता विभाग के वसूली / बिक्री अधिकारियों तथा परिसमापकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 26 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2019 तक विषय विशेषज्ञ श्री श्रीकुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री भुवन गुप्ता, तहसीलदार, म.प्र. निर्वाचन आयोग, श्री जे.पी. गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता, श्री डी.के. सक्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री प्रेम द्विवेदी, उपायुक्त, सहकारिता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में इंदौर संभाग तथा नर्मदापुरम संभाग के 27 अधिकारियों ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिले चार राष्ट्रीय पुरस्कार

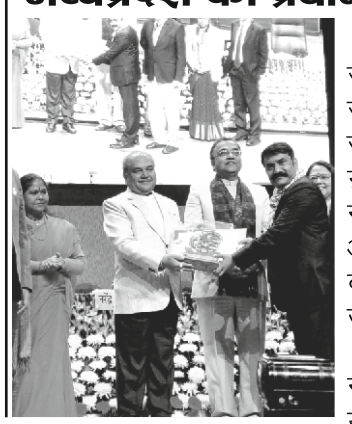

भोपाल। मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चार राष्ट्रीय अवॉर्ड प्रदान किये हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित समारोह में एम.पी.आर.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमाकांत उमराव को ये पुरस्कार प्रदान किये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री उमराव ने बताया कि प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कराये गये कार्यो की उत्तम गुणवत्ता के लिए देश में प्रथम, सड़क मार्गो के संधारण कार्य के लिये प्रथम अधिकतम लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए तृतीय और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए तृतीय पुरस्कार मिला है। पुरस्कार समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सचिव ग्रामीण विकास श्री अमरजीत सिन्हा, अपर सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय तथा एम.पी.आर. आर.डी.ए. के प्रमुख अभियंता श्री पी.के. निगम उपस्थित थे।

एक वर्ष में 5690 करोड़ की 36 लघु सिंचाई योजनाएं मंजूर

भोपाल। प्रदेश में एक वर्ष में 5690 करोड़ रुपये लागत की 36 लघु सिंचाई योजनाएँ (एक वृहद सिंचाई योजना) स्वीकृत कर राज्य सरकार ने खेती को समृद्ध बनाने के संकल्प को पूरा किया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी अवधि में 74 लघु योजनाए भी पूर्ण की गई हैं, जिनसे 26 हजार 277 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ी है। इसके अलावा, निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है। इसी अवधि में सी.बी.आई.बी. नई दिल्ली द्वारा प्रदेश की मोहनपुरा बहुउद्देश्यीय परियोजना को समय पर पूर्ण करने तथा निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करने पर ''बेस्ट कंस्ट्रक्शन एन्टिटी'' (सर्वश्रेष्ठ निर्माण इकाई) के रूप में पुरस्कृत किया गया है।

5 साल में 12 लाख हे. में सिंचाई क्षमता का लक्ष्य

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंचाई क्षमता में अगले 5 साल में 12 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाएगी। इस तरह सिंचाई की वर्तमान क्षमता 33 लाख हेक्टेयर को बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। साथ ही, अगले 5 साल तक सिंचाई जल की दरों को स्थिर रखा जाएगा। राज्य सरकार ने जल उपभोक्ता संस्थाओं के निर्वाचन की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है।

जलाशयों की पूर्ण भराव जल क्षमता अर्जित करने के लिये नई नीति

प्रदेश के जलाशयों की पूर्ण जलभराव क्षमता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने नई नीति बनाई है। जलाशयों की सिल्ट एवं रेत को अलग–अलग कर सिल्ट किसानों को दी जाएगी। रेत का विक्रय कर राजस्व प्राप्त किया जाएगा। खेती के विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर भी विचार किया जा रहा है।

जल क्षति रोकने के लिये नहरों की लाइनिंग

प्रदेश में किसानों की सहभागिता से मार्च 2019 की स्थिति में 2064 जल उपभोक्ता संस्थाओं के माध्यम से 24 लाख 74 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। नवीन योजनाओं में नहरों में लाइनिंग का प्रावधान किया गया है। इससे जल की क्षति को रोकने में मदद मिलेगी। तवा एवं बारना वृहद परियोजनाओं में पिछले एक वर्ष में क्रमशः 116.34 किलोमीटर एवं 113.51 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य किया गया है। वर्तमान में 114 लघु सिंचाई योजनाओं के डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई भी जारी है।

बांधों के जल से तालाबों का भराव

प्रदेश में जल की मांग एवं बांधों में अतिरिक्त जल की उपलब्धता के आधार पर गंगा–कछार रीवा के 112 तालाबों को बाणसागर के बांध के जल से भरा जा रहा है। इसी तरह, यमुना कछार ग्वालियर के 14 तालाबों को विभिन्न नहरों से तथा टीकमगढ़ जिले में हरपुरा नहर से क्षेत्र के 10 तालाबों को भरा जा रहा है। जल संसाधन विभाग के आधिपत्य के सभी चंदेल कालीन और अन्य प्राचीन तालाबों का रख–रखाव भी नियमित रूप से किया जा रहा है। छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिले के 30 प्राचीन तालाबों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

अधूरी सिंचाई योजनाओं की पूर्णता को प्राथमिकता

राज्य सरकार ने अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता दी है। प्रतिवर्ष 100 लघु सिंचाई योजनाओं को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चार वृहद और आठ मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इस प्रयासों से अब वह दिन दूर नहीं, जब पूरा मध्यप्रदेश सिंचाई के मामले में पूरी तरह आत्म–निर्भर होगा।

मत्स्य-उत्पादन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का हुआ बीमा

भोपाल। प्रदेश में मत्स्य–विकास एवं मछुआ कल्याण के लिये बीते एक साल में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वित भी किया गया। इसके फलस्वरूप मत्स्य कृषक 2 लाख टन मत्स्य–उत्पादन करने में सफल हुए। शासन की सुव्यवस्थित योजनाओं का ही परिणाम रहा कि इस दौरान प्रदेश में 163 करोड़ 25 लाख मत्स्य–बीज (स्टैण्डर्ड फ्राई) का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ। देवास के मत्स्य–कृषक श्री संदीप परदेशी को उत्कृष्ट मत्स्य–उत्पादन के लिये भारत सरकार ने विश्व मत्स्यकीय दिवस पर द्वितीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया।

जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण

मत्स्य–पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अल्पावधि ऋण के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर 6293 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। शासन ने मछुआरों एवं मत्स्य–उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करवाकर उनका जीवन सुरक्षित कर दिया हैं। नील क्रांति योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में प्रदेश में 338 केज स्थापित किए गए है। अब प्रत्येक केज से 4 से 5 टन पंगेशियस मछली का उत्पादन मिल रहा है।

मत्स्य–उत्पादन एवं विक्रय को प्रोत्साहन

मत्स्य–उत्पादकता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में अनुदान पर मत्स्य–आहार उत्पादन के लिए चार फिशफीड मिल की स्थापना की गई है। निजी क्षेत्र में मत्स्य–बीज उत्पादन एवं संवर्धन के लिये 5 हैचरी की स्थापना के लिए आवश्यक राशि प्रदान की गई है। इसी के साथ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मत्स्य–कृषकों को उत्पाद का उचित मूल्य एवं उपभोक्ता को ताजी तथा हाईजिनिक मछली उपलब्ध कराने के लिए नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों में 105 फुटकर मत्स्य–बाजारों का निर्माण भी कराया गया है।

मत्स्य महासंघ द्वारा जलाशय में कार्यरत मछुआरों को आखेटित मछली के लिये 20 करोड़ रूपये पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया। बंद ऋतु में मछुआरों एवं उनके पारिवार के सदस्यों को जीवन–यापन के लिये आजीविका सहयोग योजना में तीन करोड़ से ज्यादा राशि का

भुगतान किया गया। नाव–जाल अनुदान योजना में 5031 मछुआरों को 343 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह

मुख्यमंत्री मीनाक्षी कन्या विवाह योजना में राज्य शासन द्वारा मछुआरों की 143 कन्याओं के विवाह के लिए 28 लाख 60 हजार की राशि व्यय की गई। प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में राज्य शासन द्वारा महासंघ के जलाशय में 28 मत्स्य सहकारी समिति एवं 247 मछुआरों को कुल 21 लाख 22 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई। राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ द्वारा संचालित निषादराज छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गंभीर बीमारी अनुदान योजना, अनुग्रह योजना, मछुआ प्रशिक्षण योजना में राज्य शासन द्वारा 22 लाख 44 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में मछुआरों को प्रदान किये गये। इस तरह बीते एक साल में मछुआरों के कल्याण पर भरपूर ध्यान दिया गया।

संभवामी युगे-युगे एलबम : मानवीय मूल्यों के उत्थान की एक मार्गदर्शिका

श्रीमद्भागवत गीता सदा से ही मनुष्य के लिए प्रेरणादायी रही है। इसमें श्रीकृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व कर्म एवं चिंतन पर मार्गदर्शन दिया था जिसमें मानवता के उत्थान व कर्म को प्रधानता दी गई है। विश्व में गीता पर अनेक संतो एवं महापुरूषों द्वारा व्याख्यान व टीका किया है। इसमें संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी श्री बालगंगाधर तिलक की गीता रहस्य तथा स्वामी विवेकानंद की गीता प्रमुख है। इन सभी पुस्तकों में गीता के उपदेश एवं उसमें छुपे रहस्य को सरल भाषा में विस्तृत वर्णन कर लोक कल्याण को मुखरित किया गया है। इसी प्रयास में भोपाल निवासी डॉ दन्तु मुरली कृष्णा ने श्रीमद्भागवत गीता को सरल तथा सहज हिन्दी में गायन रूप में प्रस्तुत किया है। डॉ. कृष्णा एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा ल्यूपिन लिमिटेड कंपनी में वरिष्ठ महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है। वे संभवतः ऐसे प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने हिन्दी व तेलगु भाषा में गायन रूप में गीता को प्रस्तुत किया है। यहा पर विशेष वर्णित है कि उन्होंने स्वयं ही कर्नाटक शैली में गायन रचना तथा दिग्दर्शन किया है। इसका अंतिम मिश्रण तथा मास्टरिंग यशराज फिल्म स्टूडियों, मुम्बई में किया गया है। इस प्रयास में उन्होंने स्वयं को निधि एक करोड़ रूपये, तीन वर्ष का अथक परिश्रम को निवेश किया है। लोक कल्याण व मानव जीवन को सरसता देने के लिये थे निःशुल्क उपलब्ध है। इसका यू–ट्यूब लिंक है [https://youtube/iL7LDRfMyDw] इसमें श्रीमद् भगवत गीता के प्रभावी 108 श्लोक है। यह श्लोक मानवीय जीवन प्रबंधन व कार्यक्षेत्र को श्रेष्ठता पर आधारित है। यह एलबम मानवीय मूल्यों के उत्थान में एक मार्गदर्शिका की भूमिका में है। डॉ. कृष्णा के इस सराहनीय प्रयास पर माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार, माननीय राज्यपाल मध्यप्रदेश शासन तथा इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा सम्मान ''विशिष्ट संस्कृत सेवाव्रत्ति'' द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉ. कृष्णा को निरन्तर भारत तथा मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है।

डॉ दन्तु मुरली कृष्णा

मुझे जनता से चाहिए अपने कामकाज के आकलन का प्रमाण-पत्र : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मुझे अपने कामकाज के आकलन का प्रमाण पत्र जनता से चाहिए। प्रचार–प्रसार, होर्डिंग और ब्राडिंग के जरिए आत्म प्रशंसा करने से मैं परहेज रखता हूँ। श्री कमल नाथ ने 16 दिसम्बर 1971 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 48 साल पहले पाकिस्तान को करारी शिकस्त देते हुए एक नया राष्ट्र ''बांगलादेश'' बनाने के गौरवपूर्ण दिन का उल्लेख करते हुए कहा कि अच्छा होता अगर पूरे देश में इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता। मुख्यमंत्री ने एक निजी चैनल के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विशेष बातचीत के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश में एक वर्ष में किए गए बुनियादी बदलाव और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए।

जनता का सरकार पर विश्वास हो, यह है मेरा प्रयास

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपने एक साल के कामकाज में प्रचार–प्रसार से दूर रहकर किए गए कामों पर कहा कि मेरा विश्वास है कि हमारे कार्यों पर अंतिम मुहर जनता की लगना चाहिए। जनता की तरफ से यह बात आए कि उसे सरकार और नेतृत्व पर विश्वास है। यही प्रमाण–पत्र हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आयोजनों, अभियानों और अतिरेक प्रचार–प्रसार करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और हो, तो यह जनता के साथ धोखा है।

समय पर सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन ही हमारा लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पिछले एक साल के दौरान अपनी सरकार के कामकाज पर कहा कि काम करने के लिए मुझे अभी तक मात्र साढ़े नौ माह मिले हैं। मेरा सबसे पहला प्रयास यह था कि शासन और प्रशासन की सोच, नजरिए और दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। हम चाहे कोई भी नीति बना लें, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से समय पर न हो, तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है। इस दृष्टि से तंत्र के व्यवहार में परिवर्तन और जवाबदेही का वातावरण हमने प्रदेश में बनाया है। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, ऐसा जनता में विश्वास हो। इस दिशा में हमने ठोस प्रयास किए हैं। जो निवेश हमारे यहां पूर्व से स्थापित है, उसका विश्वास सरकार पर हो, इस दृष्टि से भी हमने काम किया है। मेरा मानना है कि जब तक हम प्रदेश में स्थापित उद्योगों में विश्वास पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहां नए निवेश आने की संभावना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस क्षेत्र में हमने सफलता हासिल की है।

माफिया मुक्त मध्यप्रदेश बनाना हमारी मंशा, टारगेट करना नहीं

मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरी के बाद माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान पर कहा कि आज हमारे प्रदेश में जितने दूध की खपत है, उतना उत्पादन भी नहीं होता। जाहिर है कि प्रदेश की जनता को मिलावटी दूध वितरित हो रहा है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को यह सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमने प्रदेश में निरंतर दूध उत्पादन सहित सभी खाने–पीने की चीजों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया है। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। माफिया के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम इसके जरिए किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। संगठित अपराध करने वाले और ब्लैकमेल करने वाले माफिया को अब मध्यप्रदेश में पनपने की इजाजत नहीं होगी। प्रदेश के विकास और जनता के हितों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जब हम प्रदेश में निवेश की बात करते हैं, तो हमें निवेशकों के लिए ऐसा वातावरण भी बनाना होगा, जिसमें वे निर्भय होकर बगैर किसी दबाव के काम कर सकें। उन्होंने कहा कि जब से हमने यह अभियान छेड़ा है, लोग निर्भय होकर माफिया के विरुद्ध शिकायतें कर रहे हैं। मेरे पास लोगों के मेल भी आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग माफिया से त्रस्त हैं। भय के कारण वे अभी तक सामने नहीं आए थे। पिछले 15 वर्षों से उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। समाज और प्रदेश सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रदेश को हम माफियामुक्त बनाकर रहेंगे।

धर्म हमारी आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने रामपथ वन गमन मार्ग बनाने और महाकाल मंदिर सहित प्रदेश के आस्था स्थलों के विकास की योजनाएँ शुरु करने पर कहा कि यह सब काम हम राजनीतिक एजेंडे पर नहीं बल्कि लोगों की आस्थाओं और मान्यताओं के सम्मान के लिए सरकार के दायित्व का ही निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का देश है। इसी विशेषता के कारण पूरा विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह सम्मान बरकरार रहे, इस दिशा में हम काम करते रहेंगे।

1971 का गौरव दिवस पूरे देश में मनाते, तो अच्छा होता

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम प्रदेश में 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीतने का विजय दिवस मना रहे हैं। हमारी सेना के तीनों अंगों के जवानों ने जिस वीरता के साथ इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, आजादी के बाद इससे बड़ा गौरव का दिन भारतवासियों के लिए हो नहीं सकता। द्वितीय विश्व–युद्धा के बाद दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ था, जब पाकिस्तान के 93 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्म–समर्पण किया था। थल सेना के अध्यक्ष जनरल मानेक शॉ के समक्ष पाकिस्तान सेना के जनरल नियाजी ने अपनी बंदूक और बेल्ट उतारकर आत्म–समर्पण किया था। पाकिस्तान के शोषण से बंगलादेशियों को मुक्त कराकर एक नए देश का गठन श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से संभव हुआ था। उन्हें पूरे विश्व ने इस सफलता पर ''आयरन लेडी'' की उपाधि दी थी। हम सभी भारतवासियों के लिए 48 साल पहले का यह दिन सबसे बड़ा गौरवान्वित करने वाला दिन था। पाकिस्तान के खिलाफ 13 दिन चले इस युद्ध में हमारी सेना के जिन जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन शहीदों के प्रति पूरे देश की सच्ची श्रद्धांजलि होती, अगर हम इसे पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाते।

विज़न डाक्यूमेंट प्रदेश के भविष्य के विकास का दस्तावेज

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अपना एक साल का कार्यकाल पूरा करने पर जारी होने वाले विज़न डाक्यूमेंट की मूल मंशा बताते हुए कहा कि हम भविष्य के मुताबिक इस प्रदेश को गढ़ना चाहते हैं। शहर, गांव, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आने वाले समय में नए परिवर्तनों के साथ विकास की रूपरेखा बने, यह हमारे विज़न डाक्यूमेंट का मूल उद्देश्य है। हम प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि विकास को लेकर हमारी सोच क्या है।

राष्ट्रवाद की भावना जोड़ने की हो, बांटने की नहीं

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राष्ट्रवाद की अपनी अवधारणा बताते हुए कहा कि हमारा देश विविधताओं का देश है। हर जाति, धर्म और संस्कृति का सम्मान हो, यही हमारा सच्चा राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए, जिससे यह संकेत और संदेश जाए कि हमारे देश के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि देश के हित में यह जरूरी है कि हम जोड़ने की राजनीति करें। हम हर उस फैसले के खिलाफ हैं, जिससे देश में वैमनस्य फैले और भाईचारे की भावना को आघात पहुंचे।

मध्यप्रदेश विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप 2020-2025

मिन्टो हाल में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया रोडमैप का विमोचन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को एक वर्ष पूरा किया है। एक वर्ष में अर्जित सफलताओं और उपलब्धि साझा करने के लिए आज आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए अगले पाँच वर्षों के लिए एक विजन दस्तावेज़ श्मध्य प्रदेश विजन–टू–डिलीवरी रोडमैप 2020–2025 'जारी किया गया। रोडमैप दस्तावेज़ का अनावरण पूर्व प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक गरिमापूर्ण समारोह में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की मौजूदगी में मिन्टो हॉल, भोपाल में हुआ।

विजन टू डिलीवरी रोडमैप – 2020–2025 के मुख्य बिन्दु

रोडमैप दस्तावेज़ का निर्माण लोगों की सामाजिक–आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और कम, मध्यम और लम्बे समय के उद्देश्यों को ध्यान में रख लोक–केंद्रित विकास प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें सभी नागरिकों विशेषकर महिलाओं, बच्चों, किसानों और अन्य हाशिए वाले समूहों का विकास सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया है।

पाँच साल के रोडमैप की कल्पना प्राथमिक (नागरिकों और संबंधित विभागों) के साथ–साथ द्वितीय (राजनीतिक नेतृत्व, फैसला लेने वाले लोगों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों) हितधारकों के साथ एक बढ़ी और विचार–विमर्श प्रक्रिया थी। यह रोडमैप विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों की जरूरतों के मुताबिक विकास संबंधी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित तरीके से शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से उनके क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ और उनकी सरकार चिन्हित क्षेत्रों पर वास्तविक रूप में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है। रोडमैप में चिन्हित मानव विकास संकेतकों और सम्बंधित लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 तक शीर्ष प्रदर्शन करने वालों प्रदेशों में से एक के रूप में बनने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। यह पिछले एक साल में सरकार द्वारा की गई पहलों और अभिनव कार्यक्रमों को पूरक बनाएगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रोडमैप में मध्य प्रदेश को श्विकास समृद्ध और खुशहाल राज्य' बनाने पर बल दिया गया है। इसके लिए, राज्य की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और लोगों के अनुकूल बनाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता रोडमैप में है।

इस रोडमैप में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक समरसता, पर्यावरणीय स्थिरता, बुनियादी ढाँचे के विकास और सुशासन के 06 मानव विकास विषयों को शामिल किया गया है। इन 6 क्षेत्रों को पुनः 11 सेक्टरों में बाँटा गया है, जो क्रमशः औद्योगिक विकास, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और पोषण, समावेशी विकास, संस्कृति, विरासत और पर्यटन, युवा कल्याण और खेल, सिंचाई, ऊर्जा और पर्यावरण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और सुशासन हैं।

रोडमैप दस्तावेज़ में मध्य प्रदेश के विश्लेषण में प्रदेश की शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों का आंकलन किया गया है। इसके बाद दस्तावेज़ बनाने के लिए अपनाये गये सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। रोडमैप के निर्माण में अपनाई गई क्रिया जैसे पृष्ठभूमि, विकास की रूप–रेखा, चहुँमुखी एजेंडा और प्रमुख क्षेत्रों और मुख्य विषयों की पहचान, प्रत्येक क्षेत्र की आकांक्षाएँ तथा आकांक्षाओं का प्राथमिकता निर्धारण इत्यादि है। सेक्टोरल प्राथमिकताएँ तय करने एवं दस्तावेज को बनाने में हितधारकों से बातचीत, विभागों से बातचीत तथा डेस्क अनुसंधान को विकसित करने के लिये अपनाये गये तरीकों का उल्लेख है। दस्तावेज़ के मुख्य अंग – पृष्ठभूमि, दृष्टि, मिशन और लक्ष्य, निगरानी योजना और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक एवं सूचकांक हैं।

इस रोडमैप के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र और विभाग के लिए व्यापक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI)' का निर्माण भी किया जायेगा जिससे प्रगति को मापने योग्य बनाने के साथ–साथ जहाँ भी जरूरी हो, सुधारात्मक कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया जा सके।

कुल मिलाकर ''मध्य प्रदेश विज़न–टू–डिलीवरी रोडमैप 2020–2025'' मध्यप्रदेश को एक संपन्न और समृद्ध राज्य बनाने के लिए लोगों की सरकार की प्रतिबद्धता है, जहाँ हर किसी की देखभाल की जाती है, उनकी आजीविका मजबूत होती है और हितों की रक्षा की जाती है।

म.प्र. का बदलता औद्योगिक परिदृश्य : आदिवासी अंचलों में बढ़े रोजगार के अवसर

इन दिनों मध्यप्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उद्योगों को विस्तार मिल रहा है। बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के कारण प्रदेश का नक्शा बदल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आदिवासी अंचल के लोगों को रोजगार के नए अवसरों के साथ उद्योग स्थापित करने के अवसर भी मिल रहे हैं।

भारत सरकार ने किया पुरस्कृत

मध्यप्रदेश में हो रहे नवाचार से प्रभावित होकर केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु फेसिलिटेशन काउंसिल को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार ने काउंसिल द्वारा एमएसएमई इकाइयों से विलंबित भुगतान की राशि के प्रकरणों में एवार्ड पारित होने के बाद देय रकम की वसूली की सराहना की है। जेम (ळमड) से क्रय पद्धति अपनाने में मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम किस्म के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप इन्वेस्टर मीट में 40 स्टार्ट अप एवं 8 इनवेस्टर्स ने भागीदारी की। इसी क्रम में स्व–रोजगार संचालित करने वाले सभी 12 विभाग को एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया गया। अब स्व–रोजगार योजना में ऋण के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मध्यप्रदेश के उत्पादों को जीआई टैग दिलवाने की कोशिश के प्रथम चरण में पाँच उत्पाद को शामिल किया गया है। इसमें जोबट जिला अलीराजपुर की दरी, बुरहानपुर की मावा–जलेबी, मुरैना की गजक, इंदौर का पोहा एवं डिंडौरी, मंडला, शहडोल तथा अनूपपुर की कोदो–कुटकी के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों के लिए पुरस्कार योजना में संशोधन कर मध्यम इकाई को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, इस पुरस्कार की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है।

मध्यप्रदेश में पहले से जटिल औद्योगिक भू–आवंटन नियम को सरल करने एवं मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन करने के साथ भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में स्टेट ऑफ इंक्यूबेटर की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार को प्रेषित किए प्रस्ताव

भारत सरकार के एमएसएमई– सीडीपी स्कीम के अंतर्गत जबलपुर में मिष्ठान एवं नमकीन कलस्टर के लिए कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर को मंजूरी मिल चुकी है। इस स्कीम में 200 एमएसएमई इकाइयों को लाभ होगा तथा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से 4200 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिये आधुनिक विनिर्माण तकनीक उपलब्ध कराने, नवीनतम विनिर्माण में मानव– संसाधनों को कुशल बनाने एवं तकनीक तथा व्यवसायिक सहायता करने के बड़े उद्देश्य के लिए भारत सरकार के सहयोग से 200 करोड़ की लागत से जबलपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित होगा। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसी क्रम में 9 औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन एवं 2 नवीन औद्योगिक इकाई बुरहानपुर में पावरलूम एवं भोपाल में आरा मिल के लिए कुल 145 करोड़ 85 लाख रुपये के अधोसंरचना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं। एस्पायर योजना में डिंडौरी जिले में लाईवली–हुड आधारित खाद्य प्र–संस्करण इन्क्यूबेशन सेंटर का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रदेश में एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कार्यालय शुरू करने, एमएसएमई के फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग, आटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग एवं टेक्सटाईल सेक्टर के चेप्टर, इंदौर एवं भोपाल में स्थापित करने तथा फेसिलिटी स्कीम में इंदौर में कॉमन फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं।

उल्लेखनीय रहा एक साल का सरकार का कार्यकाल

एक साल में 365 वचन पूरे, 164 वचन पूर्ण और 201 सतत पूरे

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने आज एक वर्ष पूरा किया। इस अवधि में प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 2018 में प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के पूर्व जारी वचन–पत्र के बिन्दुओं को पूरी शिद्दत से अमली जामा पहनाया। पिछले एक वर्ष की अवधि के पूरे 365 दिनों में सरकार को प्रतिदिन एक वचन की पूर्ति/सतत पूर्ति करने में सफलता मिली। इस अवधि में 164 वचन पर पूर्ण रूप से और 201 वचन पर सतत् पूर्ति की श्रेणी में काम हुआ।

इस प्रकार सरकार की कथनी और करनी में भेद नहीं रहा। उसने जो कहा सो किया। निर्वाचन के पूर्व जनता को दिये गये वचनों की पूर्ति की दृष्टि से पिछला एक वर्ष उल्लेखनीय रहा। इस अवधि में खासतौर से किसान–कल्याण और कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, युवा, नगरीय विकास और ग्रामीण विकास से संबंधित वचनों की पूर्ति विशेष रही।

किसान–कल्याण के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कार्यभार सम्हालने के पहले ही दिन किसानों की ऋण माफी का फैसला लिया। इस फैसले के अनुरूप प्रथम चरण में 20 लाख 22 हजार 731 ऋण खातों पर 7,154.36 करोड़ की राशि की माफी की जा चुकी है। कर्ज माफी का दूसरा चरण प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें कुल 12 लाख से अधिक ऋण खातों पर राशि रूपये 11 हजार 675 करोड़ से अधिक की माफी की जायेगी।

सरकार ने गेहूँ के विपुल उत्पादन की स्थिति में मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्य से जय किसान समृद्धि योजना भी लागू की। मक्का में फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में 896 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के लिये 3828 क्लस्टर/ समूह में जैविक खेती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सभी मंडियों में ई–अनुज्ञा (ऑनलाइन) प्रणाली लागू की गई। पहली बार किसानों को अनुदान पर कन्बाइन हार्वेस्टर प्रदान किये गये । नये 264 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना की जा रही है। उद्यानिकी और खाद्य प्र–संस्करण को भी प्रोत्साहन इस अवधि में दिया। नयी मुख्यमंत्री बागवानी और खाद्य प्र–संस्करण योजना लागू की गई। सब्जी और मसाला विस्तार योजना में अजजा और अजा वर्ग के किसानों की अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की गई। शिक्षित बेरोजगारों को उद्यानिकी फसलों के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार देने संबंधी नई नीति बनाई जा रही है।

सरकार ने अगले पाँच वर्ष में वर्तमान सिंचाई क्षमता को 33 लाख से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य निर्धारित कर काम शुरू कर दिया है। पुरानी अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ नयी सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रदेश को आवंटित 18.25 एमएएफ नर्मदा जल का उपयोग वर्ष 2024 के पूर्व किये जाने संबंधी योजनाओं पर तेजी से कार्य किया गया।

इस दौरान नगरीय विकास की योजनाओं को जन–अनुरूप बनाकर जन–भागीदारी से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। प्रचलित योजनाओं को सुव्यवस्थित कर उत्तरदायी नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में परिणाममूलक कोशिशें निरंतर जारी हैं। पिछले एक वर्ष में रूकी या अधूरी पड़ी हुई पेयजल, सीवरेज, मेट्रो आदि परियोजनाओं को समय–सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया गया है। पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था निर्मित करने की दिशा में नई योजनाएँ शुरू की गई। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शहरी गरीबों को पट्टा एवं पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सितम्बर माह में ''मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी)'' का शुभारम्भ झाबुआ से किया। भूमिहीन परिवारों को पट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। निकायों में क्लस्टर की जगह विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य–योजना लागू की गई।

शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना आरम्भ की गई । इसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्र के युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देकर क्षमता बढ़ाना तथा जीवन–यापन की फौरी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक वर्ष में 100 दिवस का अस्थायी रोजगार एवं समानुपातिक स्टाइपेंड प्रदान करना है। अभी 38 ट्रेंडों में करीब 20 हजार हितग्राही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। योजना में 18 हजार से ज्यादा पात्र हितग्राहियों को 12 करोड़ से ज्यादा की स्टाईपेंड राशि दी गई। अवैध होर्डिंग हटाये जाने की कार्रवाई की गई। मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2019 बनायी गई। इंट्रा–सिटी एवं इंटरसिटी बस सेवाओं को प्रभावी बनाया गया। राज्य शहरी आजीविका मिशन में 30 नये शहरों को जोड़ा गया।

राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा व्यवस्था कायम करने के लिये पिछले एक साल में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्हें जमीन पर उतारा। अब बच्चे स्कूल पहुँचने लगे हैं, शिक्षक भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये समर्पित हुए हैं। अकादमिक सत्र 2019–20 से पाँचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन बोर्ड पैटर्न पर किये जाने का निर्णय लिया गया। ''ऑनलाइन ट्रान्सफर'' व्यवस्था लागू कर शिक्षकों को उनकी पसंद के स्थान पर पद–स्थापना में प्राथमिकता दी गई है। अध्यापकों की शिक्षा विभाग में संविलियन की माँग को पूरा किया गया। शिक्षकों के रिक्त पदों पर 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र की जा रही है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के चुनिंदा और बेहतर शिक्षा के लिए अग्रणी प्रदेशों के समकक्ष बनने की ओर मध्यप्रदेश ने शिक्षक–छात्र अनुपात बेहतर करने के साथ मजबूती से कदम बढ़ाये हैं। आधुनिक संसाधनों से शिक्षा संस्थानों को परिपूर्ण करना, अधोसंरचना का निर्माण, बेटियों के लिए सुलभ और बेहतर शिक्षा, प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने, कौशल विकास और रोजगारमुखी शिक्षा, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति, ई–लायब्रेरी और खेल मैदान की उपलब्धता जैसी नीतियों के लागू और पूरा होने से प्रदेश का उच्च शिक्षा परिवेश रचनात्मक और विश्वसनीय बना है।

इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू कर आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली एक रूपये प्रति यूनिट देने का काम किया गया। इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू कर किसानों के लिये 10 हार्स पावर तक के पंपों पर विद्युत शुल्क 1400 रूपये से घटाकर 700 रूपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष कर दिया।

इस अवधि में प्रदेश के सुदूर अंचलों में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने और बीमारियों से जूझ रहे पीड़ितों को चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही उपचार की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा। सबके लिये सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिये सरकार के प्रयासों के नतीजे केवल एक ही वर्ष में नजर आने लगे हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जो जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देने वाला कानून बनाने जा रहा है। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति–2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में लगभग 100 संजीवनी क्लीनिक स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। 118 सिविल डिस्पेंसरी एवं 136 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स–मध्यप्रदेश आरोग्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है।

चिकित्सा की आधुनिक सुविधाओं युक्त स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के साथ समुचित संख्या में डाक्टरों की पदस्थापनाएँ की गई हैं। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिये ''मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना'' लागू करने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिये सीट्स की संख्या भी बढ़ाई गई हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और चिकित्सा शिक्षा के अध्ययन के लिये प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुचक्र के पूरी तरह से खात्मे के लिये सरकार ने एक युद्ध का ऐलान कर दिया है। मिलावटखोरों जैसे गुनाहगारों की धर–पकड़ के इस संवेदनशील संकल्प के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।

प्रदेश सरकार की नजर में पीने के लिये साफ पानी केवल जरूरत ही नहीं, बल्कि सामान्य जन का अधिकार भी है। ''राइट टू वाटर एक्ट'' लागू होने पर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहाँ लोगों को पानी का कानूनी अधिकार मिलेगा। पिछले एक वर्ष में सड़कों के निर्माण, मजबूतीकरण और नवीनीकरण के अनेक कार्य प्रदेश के विकास के लिये प्रतिबद्धता का प्रमाण रहे।

प्रदेश की नई सरकार की प्राथमिकताओं की फेहरिश्त में महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास सबसे ऊपर रहा। नई बाल संरक्षण नीति बनाई जा रही है। पोषण आहार अभियान के तहत अब बच्चों के वजन के साथ ही उम्र के अनुसार कद के मान से उसके परिवार को पोषण परामर्श दिया जा रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत राज्य किशोर न्याय नियम बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अब दुष्कर्म पीड़िता बालिका अथवा महिला से जन्म लेने वाली बालिका को भी लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह – निकाह योजना की राशि 28,500 से बढ़ाकर 51 हजार रूपये की गई है।

राज्य सरकार द्वारा गाँवों के विकास के लिये विभिन्न नवाचारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी घर शौचालयविहीन ना रहे, इसलिये शौचालयविहीन घरों का चिन्हांकन किया जा रहा है। नदियों के पुनर्जीवन हेतु नदी पुनर्जीवन योजना बनाई गई, जिसमें 40 जिलों में 40 नदियों का चयन किया गया। इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1000 गौ–शाला निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कुल 903 गौ–शालाओं का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका।

अपात्र बसाहटों के लिये एकल/ दोहरी सम्पर्कता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं रख–रखाव के क्रियान्वयन के लिये नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलन में है। एकल सम्पर्कता विहीन राजस्व ग्रामों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना विकास निधि से डामरीकृत सड़क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। ष्महात्मा गांधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजनाष् में पक्के निर्माण कार्यों में 50 प्रतिशत राशि सी.सी. सड़क पर व्यय करने की अनिवार्यता समाप्त कर कुल व्यय सीमा 75 प्रतिशत की गई। पीएमजी एसवाय–एक एवं दो में 3319 किमी लंबाई सड़कें पूर्ण की गई। म.प्र. ग्रामीण सम्पर्कता परियोजना में 2752.51 कि.मी. लंबाई की बी.टी./सी.सी. मार्गों का निर्माण पूर्ण किया गया। अन्य योजनाओं में भी 580 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में दो लाख 23 हजार आवास पूर्ण किये गये। सर्वे में छूट गये तीन लाख से अधिक शौचालयविहीन घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। सवा 5 लाख से ज्यादा परिवारों को संगठित कर करीब 50 हजार स्व–सहायता समूहों का गठन किया गया। इन समूहों को 37 हजार प्रकरणों में बैंकों से 232 करोड़ रूपये का ऋण दिलाया गया। मनरेगा में साढ़े 12 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये।

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

1 जनवरी, 2020

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

जनवरी 2020

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	

फरवरी 2020

रविवार		2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29

मार्च 2020

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

अप्रैल 2020

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	
शनिवार	4	11	18	25	

मई 2020

रविवार	31	3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30

जून 2020

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	

जुलाई 2020

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	

अगस्त 2020

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार	31	3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29

सितम्बर 2020

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरुवार	3	10	17	24	
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	

नवम्बर 2020

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

अक्टूबर 2020

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	31

दिसम्बर 2020

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरुवार	3	10	17	24	31
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	

समस्त रविवार, 26 जनवरी-गणतंत्र दिवस, 9 फरवरी-संत रविदास जयंती, 21 फरवरी - महाशिवरात्रि, 10 मार्च होली, 25 मार्च- गुड़ीपड़ा/चैती चांद, 2 अप्रैल-रामनवमी, 6 अप्रैल - महावीर जयंती, 10 अप्रैल - गुड फ्रायडे, 14 अप्रैल - डॉ. अम्बेडकर जयंती/वैशाखी, 26 अप्रैल परशुराम जयंती, 7 मई - बुद्ध पूर्णिमा, 25 मई - ईद-उल-फित्र, 1 अगस्त - ईदुज्जुहा, 3 अगस्त - रक्षाबंधन, 9 अगस्त-आदिवासी दिवस, 12 अगस्त - जन्माष्टमी, 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस, 30 अगस्त - मोहर्रम, 2 अक्टूब - गांधी जयंती, 25 अक्टूबर - दशहरा, 30 अक्टूबर- मिलाद-उन-नबी, 31 अक्टूबर - महर्षि बाल्मीकी जयंती, 14 नवम्बर - दीपावली, 30 नवम्बर - गुरुनानक जयंती, 25 दिसम्बर - क्रिसमस।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा

डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।